# HON'BLE SUPREME COURT OF INDIA

*is organising*



# SAMADHAN SAMAROH, 2026

which has already started from 21.04.2026
for

**Special Lok Adalat at Supreme Court of India to be held on**



## 21st, 22nd and 23rd August, 2026

**FOR THE CASES PENDING BEFORE HON'BLE SUPREME COURT OF INDIA ONLY**

**Following categories of cases would be taken up in the Lok Adalat with the consent of the parties:**

- Banking & Insurance Cases
- Civil Matters
- Motor Accident Compensation Cases
- Consumer Disputes and RERA Cases
- Family Disputes
- Commercial & Arbitration Cases
- Negotiable Instruments Act Cases
- Land Acquisition Matters
- Service Matters of Govt. Servants
- Rent Control and Public Premises (Eviction) Act Cases
- Labour and Industrial Matters
- Transfer Petitions
- Any other case wherein settlement is lawful including Quasi criminal cases or compoundable offences

**Benefits of Lok Adalat**

- No court fee is charged. If court fee has already been paid, the amount will be refunded.
- Simple and speedy settlement of disputes with the consent of parties.
- Orders of Lok Adalat are final and cannot be challenged.

**Judicial officers & Trained Mediators shall hold Pre-Lok Adalat sittings physically or through video conferencing at the Hon'ble High Court of Delhi & Delhi District Courts to facilitate the parties in reaching amicable written settlement.**

*(Services shall be free of cost)*

Advocates & Parties can access the list of referred cases originating within the jurisdiction of Delhi on the website of Delhi State Legal Services Authority through the following link or given QR code: https://dslsa.org/list-of-cases-referred-for-special-lok-adalat-at-supreme-court-of-india/

If your case is pending in Hon'ble Supreme Court of India or is contemplated to be filed in Supreme Court of India and is not among the already referred cases, you may have your case referred by submitting the details through the following Google Form link or given QR code: https://forms.gle/d5paBNL7ywpQ3jiN6

**For any query, you may contact either of the following:-**

| SUPREME COURT OF INDIA | NALSA | SCLSC | DSLSA | DHCLSC |
|---|---|---|---|---|
| One Stop Centre, Contact No.: 011-23112428, 011-23112528, 011-23116464, 011-23116465, 011-23115652 Email: speciallokadalat2026@sci.nic.in | Contact No.: 011-23382778, 011-23382121, Toll Free No. 15100 Email: nalsa-dla@nic.in | Contact No.: 011-23381257, 011-23116353, 011-23116354 Email: sclsc@nic.in | Contact No.: 011-23232124, 011-23232781, Email: lokadalatwing-dslsa@nic.in, Toll Free Helpline : 1516 (24*7) | Contact No.: 011-23383418, 011-43010101 Extension-4381 Email : dhclsc-dhc@nic.in |

*Advocates & parties may also contact their nearest District Legal Services Authorities located in all District Courts in Delhi.*

**RAJEEV BANSAL**
MEMBER SECRETARY
DELHI STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY
Website: www.dslsa.org

# माननीय सर्वोच्च न्यायालय
## आयोजित कर रहा है



# समाधान समारोह – 2026

**जिसकी शुरुआत 21.04.2026 से हो चुकी है**

**इसके अंतर्गत भारत के सर्वोच्च न्यायालय में विशेष लोक अदालत का आयोजन निम्नलिखित तिथियों पर किया जाएगा**



# 21, 22 एवं 23 अगस्त, 2026

**यह समारोह भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित मामलों के लिए आयोजित किया जा रहा है**

## निम्नलिखित प्रकार के मामले लिए जायेंगे:

- बैंकिंग और बीमा मामले
- सिविल मामले
- मोटर दुर्घटना मुआवजा मामले
- उपभोक्ता विवाद एवं रेरा मामले
- पारिवारिक विवाद
- वाणिज्यिक एवं आर्बिट्रेशन मामले
- चेक बाउंस मामले
- भूमि अधिग्रहण मामले
- सरकारी कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामले
- किराया नियंत्रण एवं सार्वजनिक परिसर (बेदखली) अधिनियम के मामले
- श्रम और औद्योगिक मामले
- स्थानांतरण याचिकाएँ
- कोई भी अन्य मामले जिसमें समझौता विधिसम्मत हो व कंपाउंडेबल एवं अर्ध-आपराधिक मामले

## लोक अदालत के लाभ

- कोई कोर्ट फीस नहीं ली जाती। यदि कोर्ट फीस पहले से जमा है, तो वापस कर दी जाएगी।
- पक्षकारों की सहमति से विवादों का सरल एवं शीघ्र निपटारा।
- लोक अदालत के निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होते हैं, जिनके विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती।

**न्यायिक अधिकारी और प्रशिक्षित मध्यस्थ, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय और दिल्ली जिला न्यायालयों में लोक अदालत से पहले की पूर्व बैठकें व्यक्तिगत रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित करेंगे ताकि पक्षों को सौहार्दपूर्ण लिखित समझौते तक पहुंचने में सुविधा हो।**

*(यह सेवा पूर्णतः निःशुल्क होगी)*

**अधिवक्ता और पक्षकार दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण की वेबसाइट पर दिए गए लिंक या क्यूआर कोड के माध्यम से दिल्ली में फाइल हुए तथा रेफर हुए मामलों की सूची देख सकते हैं।**

**https://dslsa.org/list-of-cases-referred-for-special-lok-adalat-at-supreme-court-of-india/**

**यदि आपका मामला भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है या सर्वोच्च न्यायालय में दायर किए जाने की संभावना है और पहले से रेफर मामलों में शामिल नहीं है, तो आप निम्नलिखित गूगल फॉर्म लिंक या दिए गए क्यूआर कोड के माध्यम से विवरण देकर अपने मामले को रेफर करवा सकते हैं: https://forms.gle/d5paBNL7ywpQ3jiN6**

## किसी भी प्रकार की जानकारी/ प्रश्न के लिए, आप निम्नलिखित में से किसी से भी संपर्क कर सकते हैं:-

**भारत का सर्वोच्च न्यायालय**
वन स्टॉप सेंटर, दूरभाष नं.:
011-23112428, 011-23112528,
011-23116464, 011-23116465,
011-23115652
ईमेल:
speciallokadalat2026@sci.nic.in

**राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण (NALSA)**
दूरभाष नं.:
011-232382778,
011-23382121
टोल फ्री नंबर: 15100
ईमेल: nalsa-dla@nic.in

**सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी**
दूरभाष नं.:
011-23381257,
011-23116353,
011-23116354
ईमेल: sclsc@nic.in

**दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण (DSLSA)**
दूरभाष नं.: 011-23232124,
011-23232781, ईमेल:
lokadalatwing-dslsa@nic.in
टोल फ्री हेल्पलाइन: 1516 (24×7)

**दिल्ली उच्च न्यायालय विधिक सेवाएं समिति (DHCLSC)**
दूरभाष नं.: 011-23383418,
011-43010101
(एक्सटेंशन-4381)
ईमेल: dhclsc-dhc@nic.in

*अधिवक्ता और पक्षकार दिल्ली के सभी जिला न्यायालयों में स्थित अपने निकटतम जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण (DLSA) से भी संपर्क कर सकते हैं।*

**राजीव बंसल**
सदस्य सचिव
दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण

वेबसाइट: www.dslsa.org